MR. CHAIRMAN: Now you have brought it to the notice of the House. Tomorrow you can give a formal notice.

श्री जार्ज फर्नांडीज : मुझे यह सवाल उठाना पड़ेगा ।

श्री रामअवतार शास्त्री : औचित्य क्या है, यह तो इनको बताना चाहिए ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, the Deputy Speaker has given a ruling earlier that unless he gives notice, he cannot raise such things on the floor of the House.

श्री रामअवतार शास्त्री : (पटना) : आप लोगों की तनख्वाह बढ़ा दें, नहीं तो लोग खा नहीं सकेंगे ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: What he said should not go on record.

SHRI GEORGE FERNANDES: Why, Sir? It is part and parcel of record.

MR. CHAIRMAN: I have not said that it will not go on record.

SHRI GEORGE FERNANDES: The Minister should not arrogate to himself the powers of the Chairman.

MR. CHAIRMAN: Order please. I have called Shri Jaipal Singh Kashyap.

(i) STEPS FOR SETTING UP OF INDUSTRIES FOR CREATION OF EMPLOYMENT IN AONLA LOK SABHA CONSTITUENCY.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : आंवला लोक सभा चुनाव क्षेत्र जिसमें बदायूं जिले के दातागंज व बिनावर चुनाव क्षेत्र आते हैं और बरेली जिले के आंवला मुमहा एवं फरीदपुर चुनाव क्षेत्र आते हैं। ये कुछ छोटे से कस्बों को छोड़ कर 15 लाख की आबादी वाला क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है जिस क्षेत्र में एक भी कारखाना, उद्योग धंधा व रोजगार दिलाने के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं । इस क्षेत्र में कृषि ही मुख्य धंधा है, परन्तु आवागमन के साधन व राहत की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता । इस क्षेत्र के लोगों की सदैव से मांग रही है कि उनको कुछ महत्वपूर्ण उद्योग धंधे स्थापित किये जायें । चापट एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई कृषि फसल उत्पन्न नहीं होती। छोटी और बड़ी रेलवे लाइन के मध्य और रामगंगा और अरेल नदी के मध्य स्थित है, जहां पर रसायनिक खाद का कारखाना स्थापित करके यहां के लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है और इस क्षेत्र का उत्पादन हो सकता है । इसके अतिरिक्त बिनावर व दातागंज, फरीदपुर में व आलमपुर जाफराबाद में चीनी मिलों की स्थापना आवश्यक है । इसके अलावा कताई कारखाने भी आसानी से चलाये जा सकते हैं और डिग्री कालेज व मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज भी स्थापित होना आवश्यक है । मैं इस क्षेत्र के नागरिकों की उपरोक्त मांगों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पर अविलम्ब उचित कार्यवाही करें ।

(ii) DRINKING WATER PROBLEM IN THE HILLY DISTRICTS OF UTTAR PRADESH

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा): उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में पेयजल की स्थिति दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है । स्थानीय ग्रामवासियों को 4, 5 किलोमीटर तक की दूरी से पानी लाने के लिए सय करनी पड़ती है जिसमें उनका अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है । इस जटिल समस्या के निदान के लिए शासन को तत्काल निम्न कदम उठाने चाहिए :

1. उ० प्र० शासन को एक अरब रु० इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु उपलब्ध करवाया जाये। इस कार्य में वर्ल्ड बैंक व जीवन बीमा निगम आदि ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं का सहयोग भी किया लिया जाये।

2. पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिस अभियंत्रण सेवा को उपयोग में लाया जाता है योजना की सफलता के लिए उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये क्योंकि वर्तमान समय में इस अभियंत्रण सेवा के पास न तो पर्याप्त अभियंता हैं और न उनके अभियंताओं में सार्वजनिक हित के लिए समर्पण की भावना है।

3. यहां अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधानार्थ योजनायें लिफ्ट पेयजल योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है जिनके लिए सतत् विद्युत् की आवश्यकता पड़ती है जो कि इन योजनाओं को उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों को विद्युत् कटौती से मुक्त रखने हेतु प्रान्त सरकार को कहा जाये तथा दीर्घकालीन उपाय के रूप में इस क्षेत्र में उपलब्ध अपरिमित जल विद्युत् सम्भावनाओं को योजनाबद्ध कर उपयोग में लाया जाये।

4. पिंडरघाटी योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश शासन को कहा जाय तथा जल समस्या और अधिक विकट न हो इस हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के कटान पर पूर्णतः रोक लगा दी जानी आवश्यक है व सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत इस क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले जल संचक् वृक्षों का रोपण किया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय योजना मंत्री जी से उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(iii) NEED TO CONSTRUCT A BY-PASS NEAR RAILWAY OVER-BRIDGE IN KOTA RAJASTHAN

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय मैं रेल मंत्रालय का ध्यान कोटा राजस्थान में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज की तरफ दिलाना चाहूंगी। इस ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य सन् 1977 से आरम्भ हुआ। इस ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य आरम्भ करने के साथ ही बाई-पास भी रेल मंत्रालय द्वारा बनवाया जाना चाहिए था परन्तु बाई-पास न बनने से तीव्र वाहनों को 20 या 25 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है। इससे 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं। आज देश में पैट्रोलियम पदार्थ की पहले ही कमी है, 20 25 किलो-मीटर अनावश्यक दूरी पार करने से कितनी अतिरिक्त हानि पैट्रोलियम पदार्थ की हो रही है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। गरीब बैलगाड़ी वाले तथा छकड़ा गाड़ी वालों को अनावश्यक दूरी पार करने में कितना समय तथा श्रम लगाना पड़ रहा है।

कोटा राजस्थान की जनता इससे अत्यधिक परेशान है। औद्योगिक नगर कोटा के व्यक्तियों को कितनी श्रम तथा धन की हानि हो रही है इसका अंदाजा लगाकर रेल मंत्रालय तुरन्त कार्यवाही करे। इस निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के पास ही बाई-पास अवश्य बनवा दें या फिर सम्बन्धित विभागों को आदेश दे कर इस समस्या का समाधान करें। औद्योगिक नगर कोटा के व्यक्तियों की कठिनाई का ध्यान रख कर तुरन्त कार्यवाही कराई जाये।

(iv) NEED FOR IMPLEMENTATION OF CHILD WELFARE PROGRAMMES IN KALAHANDI DISTRICT OF ORISSA

SHRI RASA BEHARI BEHARA (Kalahandi): Under the Integrated